(घ) यदि नहीं, तो इन केन्द्रों को शीघ्र चालू करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी० एम० सईद): (क) आकाशवाणी ने देश के 90% क्षेत्र और 97.3% जनसंख्या को कवर किया है जबकि दूरदर्शन ने 68.4% क्षेत्र और 85.4% जनसंख्या को कवर किया है। आकाशवाणी का हिसार में एक 6 कि०वा० एफ० एम० ट्रान्समीटर बहुउद्देशीय स्टूडियो, प्राप्ति सुविधा और स्टाफ क्वार्टर स्थापित करने का प्रस्ताव है, दूरदर्शन के पास वहां एक अल्प शक्ति टी०वी० ट्रान्समीटर है।

(ख) आकाशवाणी द्वारा हिसार की स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान, क्रमशः 28.35 लाख रुपए और 34.00 लाख रुपए की राशि उद्दिष्ट की गई है। दूरदर्शन के पास हिसार के लिए वर्तमान में कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

(ग) और (घ) 1996-97 के दौरान आकाशवाणी की स्कीम के तकनीकी रूप से तैयार हो जाने की संभावना है।

Power Project by Japanese Firm

98. SHRI RAM NATH KOVIND: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item published in the 'Hindustan Times' dated the 8th February, 1996 under the caption "Japanese Firm plans powers project in India";

(b) if so, the details in this regard and whether Government have approved the proposal;

(c) if so, the terms and conditions of the collaboration agreement; and

(d) the place where the power project is likely to be set up and to what extent power production is likely to increase as a result thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL): (a) Yes, Sir.

(b) There is no proposal under consideration for setting up a 37,000 KW Power project in India at a cost of 10 billion dollars by Japanese industrial house, as reported in the news item.

(c) and (d) Do not arise in view of reply to (b) above.

गुजरात को विभिन्न राज्यों द्वारा विद्युत आपूर्ति

99. **श्री अनंतराय देवशंकर दवे**: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन-कौन से राज्य गुजरात को विद्युत की आपूर्ति करते हैं और प्रत्येक राज्य द्वारा प्रतिदिन कितनी मात्रा में विद्युत आपूर्ति की जाती है और किन-किन दरों पर;

(ख) इन राज्यों द्वारा आपूर्त की जा रही विद्युत के वितरण की प्रणाली किस प्रकार तैयार की जा रही है; और

(ग) सरकार गुजरात हेतु विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति देने का विचार रखती है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल): (क) अपने विद्युत उत्पादन केन्द्रों से विद्युत प्राप्त करने के अलावा अपनी विद्युत संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गुजरात, क्षेत्र में केन्द्रीय स्टेशनों से भी अपने हिस्से की विद्युत प्राप्त करता है। अप्रैल, 95-जनवरी, 96 की अवधि के दौरान गुजरात द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र के स्टेशनों से वस्तुतः प्राप्त की गई विद्युत की अपेक्षा हकदारी का ब्यौरा निम्नवत है:

(सभी आकंड़े निवल मि०यू० में)

	पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय परियोजनाओं के नाम	अप्रैल, 95 से जनवरी, 96 तक	
		हकदारी	वस्तुतः प्राप्त
1.	कोरबा एसटीपीएस	2672.2	3512.1
2.	विंध्याचल एसटीपीएस	1861.5	2068.6
3.	कवास गैस	566.7	467.2
4.	गंधार गैस	817.7	558.9
5.	तारापुर एपीएस	625.6	625.6
6.	ककरापाड़ एपीएस	618.6	496.7
	जोड़	7162.3	7729.1

उपरोक्त के अलावा गुजरात ने पड़ौसी उत्तरी क्षेत्र से 107.7 मिलियन यूनिट तक की सहायता प्राप्त की है।

(ख) यद्यपि, क्षेत्र में राज्यों को केन्द्रीय विद्युत स्टेशनों से सहमत फार्मूले के अनुसार विद्युत का आवंटन किया जाता है, तथापि, एकीकृत ग्रिड प्रचालन में राज्य कभी-कभी अपने हिस्से से अधिक अथवा कम विद्युत प्राप्त कर सकते हैं। उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों के बीच इस प्रकार के अन्तःक्षेत्रीय विद्युत अंतरण के लिए टैरिफ के बारे में इनके बीच विपक्षीय रूप से सहमति होती है।

((ग) 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली गुजरात की कोई भी विद्युत परियोजना जिसके निवेश के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदन किए जाने की सिफारिश की गई हो, ऐसी कोई परियोजना योजना आयोग में लम्बित नहीं है। विभिन्न विद्युत परियोजनाओं को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने एक विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण किया है, जिसकी अनुपालना किए जाने पर अपेक्षित स्वीकृति समयबद्ध रूप से प्रदान की जाती है। चार परियोजनाओं, यथा जी पी सी एस की सोगा लिग्नाइट और खारसलिया लिग्नाइट, जीईबी की गुजरात तटीय परियोजना और एनटीपीसी की कवास-2 परियोजना के लिए इस प्रकार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं।

हथकरघा और विद्युतकरघा एककों का बंद किया जाना

100. **श्री अजीत जोगी:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उचित मूल्यों पर सूती धागा उपलब्ध न होने के कारण विद्युत से हथकरघा और विद्युतकरघा एकक धीरे-धीरे बंद होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में आज तक बंद किये गये ऐसे एककों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या देश में सूती की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए सरकार ने इसके आयात में कोई छूट देने की घोषणा की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सूती धागे के निर्यात पर प्रतिबंध न लगाए जाने के क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) जी नहीं। हथकरघा और विद्युतकरघा एककों की अर्थ क्षमता अनेक कारकों पर निर्भर करती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। बन्द पड़े एककों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) सूती यार्न का आयात ओ जी एल के अन्तर्गत है।

(घ) सूती यार्न का निर्यात विनियमित होता है तथा हथकरघा और विद्युतकरघा बुनकरों के हितों को ध्यान में